- 20th Year
- Issue: 113
- 24.08.2026 (MONDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

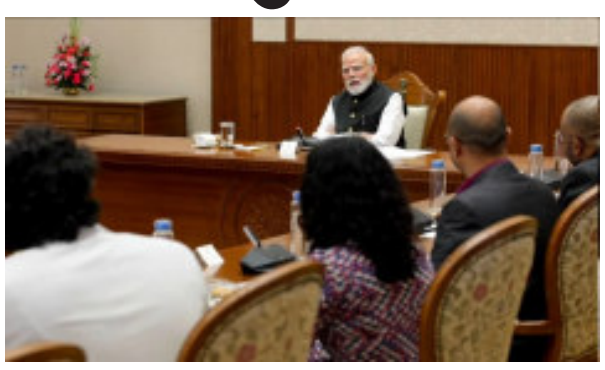

पीएम मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से की मुलाकात, बोले-दुनिया का टैलेंट भारत लाना है

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नई दिशा देने वाले स्टार्टअप्स और उनके फाउंडर्स से मुलाकात की। इस दौरान देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ढ्ढ) के बढ़ते इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती क्षमता और देश के स्टार्टअप्स के लिए मौजूद अवसरों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के पास कम लागत, बेहतरीन टैलेंट और जोखिम उठाने की क्षमता जैसी कई मजबूत खूबियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में पीएम मोदी स्पेस टेक्नोलॉजी और भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम पर अपनी बात रखते नजर आए। स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से

बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास स्पेस सेक्टर में एक बेहतरीन कॉमर्शियल मॉडल बनाने की क्षमता है। उन्होंने भारत की कम लागत और प्रतिस्पर्धी क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि टैलेंट के मामले में देश के पास कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों की रिस्क लेने की क्षमता को भी भारत की बड़ी ताकत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को स्पेस सेक्टर में ऐसा माहौल और पहचान बनानी चाहिए, जिससे दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग भारतीय कंपनियों की ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल अपने देश के टैलेंट का इस्तेमाल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए जो दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को भारत की ओर खींच सके। इससे भारतीय स्पेस कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'हैप्पी नेशनल स्पेस डे!' लिखते हुए भारत के युवाओं और इनोवेटर्स से बड़े सपने देखने, ज्यादा इनोवेशन करने और नई सीमाओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के स्पेस सेक्टर की युवा ऊर्जा से मिलकर उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्होंने युवा उद्यमियों और इनोवेटर्स की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में कदम रखा, जोखिम उठाया और लगातार बेहतर करने की कोशिश की। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसका असर देश के तेजी से विकसित होते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम में दिखाई दे रहा है। आज भारत में कई स्टार्टअप सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेस डेटा, लॉन्च व्हीकल और दूसरी आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं।

इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी कंपनियों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत का एक उदाहरण हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस भी है। इसी साल जुलाई में कंपनी के प्राइवेट रॉकेट विक्रम-१ ने अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा। विक्रम-१ की सफलता को भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारतीय स्टार्टअप अब केवल स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रॉकेट और लॉन्च व्हीकल जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं। पीएम मोदी की स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत अपने स्पेस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ ढ्ढ, सैटेलाइट डेटा और निजी लॉन्च सेवाओं का विस्तार आने वाले समय में इस क्षेत्र को और बड़ा बना सकता है। भारत के सामने अब चुनौती केवल अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल स्पेस हब बनने की है जहां दुनिया के निवेशक, कंपनियां, वैज्ञानिक और टैलेंट आकर्षित हों।

भारत बनेगा पोत निर्माण का वैश्विक केंद्र

राजनाथ सिंह ने बंगाल में 3,500 करोड़ की योजनाओं की रखी नींव

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कोलकाता से ऑनलाइन माध्यम से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की पांच विस्तार योजनाओं की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं में जीआरएसई की तीन और यंत्र इंडिया की दो विस्तार योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इन पांच परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा, भारत में पोत निर्माण का वैश्विक केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में एक शून्यता आ रही है और भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये

नई परियोजनाएं राज्य में विकास के एक नए दौर की शुरुआत करेंगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में कारखानों के बंद होने और तालाबंदी की खबरों की जगह अब नई परियोजनाओं की शुरुआत ने ले ली है। ये परियोजनाएं न सिर्फ रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देंगी, बल्कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी लाएंगी। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि जीआरएसई ने युद्धपोत बनाने और उनकी मरम्मत करने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता के साथ लीज समझौता किया है। इस समझौते के तहत हुगली नदी के दोनों किनारों पर दो छोटे शिपयार्ड और रायचक में नदी के किनारे 32 एकड़ जमीन ली गई है। अधिकारी ने आगे बताया कि ये परियोजनाएं जीआरएसई की कार्य क्षमता को मजबूत करेंगी। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं से राज्य के औद्योगिक माहौल को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी और सहायक उद्योगों, खासकर एमएसएमई सेक्टर को काम के अधिक अवसर मिलेंगे।

अमित शाह ने सिलिगुड़ी कोरीडोर की सुरक्षा समीक्षा की, पूर्वी सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर जोर

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और केंद्रीय बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा का जायजा लिया गया और मुख्य रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 'चिकन नेक' भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य मकसद सीमा पर निगरानी बढ़ाना, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस एवं प्रशासन के बीच तालमेल बेहतर करना तथा 'ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। अधिकारियों ने बताया कि

भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) की गतिविधियों, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अवैध घुसपैठ और सीमा से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जैसे केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) के तहत स्टैंडिंग फोकस ग्रुप ऑन सिलिगुड़ी कॉरिडोर (एसएफजी-एससी) ने अब तक हुई प्रगति और कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपनी सिफारिशों पर प्रस्तुति दी।

पोती से दुष्कर्म का 70 वर्षीय आरोपी दादा गिरफ्तार, पीड़िता गर्भवती

हाथरस २३/०८ (संवाददाता): उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 16 वर्षीय पोती से कथित दुष्कर्म के आरोप में 70 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लड़की ढाई महीने की गर्भवती है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया कि उसके दादा ने करीब तीन महीने तक उससे दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। लड़की की मां का निधन हो चुका है। वह अपने पिता और दादा के साथ रहती है।

लड़की का आरोप है कि पिता के काम पर चले जाने के बाद दादा उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। लड़की को पेट दर्द की शिकायत पर शनिवार को उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाया गया, जहां उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। शिकायत में लड़की ने कहा है कि वह करीब तीन-चार महीने पहले अपने मामा के यहां से सिकंदराराऊ वापस आई थी।

उसने आरोप लगाया 20 जून से उसके दादा ने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित पाठक ने बताया कि लड़की को जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था जहां उसके ढाई महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कालाहांडी में हाती नदी के उफान से गांवों में घुसा पानी, स्कूल बंद

भुवनेश्वर २३/०८ (संवाददाता): ओडिशा में भारी बारिश के बीच रविवार को राज्य के कालाहांडी जिले में हाती नदी के तटबंधों में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली। अधिकारियों ने बताया कि इस स्थिति को देखते हुए दो अन्य जिला प्रशासन ने विद्यालयों में अगले दो दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा के कई जिलों में 26 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इंद्रावती परियोजना के मंगलपुर बैराज से 412 क्यूसेक पानी हाती नदी में छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि हाती नदी पहले से

ही उफान पर थी, जिसकी वजह से आज सुबह इसके तटबंधों में अचानक बाढ़ आ गई। एक अधिकारी ने बताया कि कालाहांडी जिले के कलमपुर प्रखंड के तहत तलपाड़ा, बांकापाला और जामपदार गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) विजय कुमार मरांडी के नेतृत्व में प्रशासन ने पारुआगुडा और बोडलबंध गांवों से 293 लोगों को सुरक्षित निकाला और उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए विभिन्न जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि नवरंगपुर के सभी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र तथा भद्रक के संवेदनशील इलाकों के 89 विद्यालय सोमवार को बंद रहेंगे। राज्य के कई इलाकों में आज सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई।

केरलम के ओणम उत्सव में 10 राज्यों के 160 लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

तिरुवनंतपुरम २३/०८ (संवाददाता): ओणम-पर्यटन सप्ताह समारोह में हिस्सा लेने और देशभर की लोक परंपराओं को केरलम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ एक मंच पर लाने के लिए 10 राज्यों के 160 लोक कलाकार राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंच रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु के कलाकार 24 से 30 अगस्त तक होने वाले सप्ताहभर के समारोह के दौरान केरल के विभिन्न स्थानों पर अपनी पारंपरिक कला प्रस्तुतियां देंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कलाकार दो क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम पेश करेंगे। इससे त्योहार के दौरान लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों की लोक परंपराओं और कला को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। ये कलाकार 30 अगस्त को होने वाली भव्य ओणम शोभायात्रा में भी शामिल होंगे। शोभायात्रा शाम पांच बजे मनवीयम वीति से शुरू होकर ईस्ट फोर्ट तक जाएगी।

विज्ञप्ति में कहा गया कि केरलम के बाहर के कलाकारों की भागीदारी का उद्देश्य इस साल के समारोह को अधिक विविधतापूर्ण बनाना और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को एक साझा मंच पर लाना है। राज्य स्तरीय समारोह 24 से 30 अगस्त तक राजधानी में 35 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इन स्थानों पर 340 से अधिक कार्यक्रम होने हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक, केवल राज्य स्तरीय समारोहों में करीब 3,000 कलाकार और मंच के पीछे काम करने वाले कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जबकि पूरे केरलम में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 8,000 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। केरलम की पारंपरिक कला शैलियों को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। मुडियेट्टु, थोलपावाकूथु, पडयणी, अर्जुननृत्यम और पूथनुम थिरायुम जैसी पारंपरिक कलाओं की प्रस्तुतियां 25 से 30 अगस्त तक निशागंधी में होंगी।

ब्रिक्स समिट से पहले डोभाल का चीन दौरा, वांग यी के साथ सीमा विवाद पर होगी वार्ता

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को बीजिंग जाएंगे। वह अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा मुद्दे पर %विशेष प्रतिनिधियों% की वार्ता में हिस्सा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डोभाल और वांग यी के बीच मंगलवार को 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित की जाएगी।

बता दें, 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा के विवाद का हल निकालने के लिए वर्ष 2003 में विशेष प्रतिनिधि वार्ता तंत्र का गठन किया गया था। हालांकि यह तंत्र सीमा विवाद का अंतिम समाधान निकालने में अब तक पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश इसे सीमा पर तनाव दूर करने

और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया मानते हैं।

यह वार्ता नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित होने जा रहे %ब्रिक्स शिखर सम्मेलन% में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले हो रही है। दोनों पक्षों के अधिकारी चीनी राष्ट्रपति की भागीदारी को लेकर आशावादी हैं। इस दौरान ब्रिक्स से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से बैठक होने का अवसर मिल सकता है। दोनों शीर्ष नेताओं की आखिरी मुलाकात अगस्त 2025 में तियानजिन में %शंघाई सहयोग संगठन% शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

डोभाल-वांग वार्ता से ठीक पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही चीन के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंधों की पहली शर्त है। जयशंकर ने कहा कि 2020 से 2024 के बीच दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजरे, जो मुख्य रूप से सीमा पर पैदा हुई स्थितियों का परिणाम था। उन्होंने दोहराया कि सीमा की स्थिति ही काफी हद तक दोनों देशों के समग्र संबंधों का भविष्य तय करेगी। हाल के हफ्तों में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधियों की खबरें सामने आई थीं।

इन रिपोर्टों के बीच 12 अगस्त को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने दावा किया था कि भारत-चीन सीमा पर स्थिति फिलहाल सामान्य और स्थिर है। गुओ ने बताया कि दोनों देशों ने परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 36वीं बैठक की है, जिसमें संवाद बनाए रखने पर सहमति बनी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 11 अगस्त को कहा था कि भारत सीमाई मुद्दों को अत्यंत गंभीर मानता है और एलएसी पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक स्थलों के नाम बदलने की चीन की कोशिशों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। नई दिल्ली ने साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है और इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। चीन, जो अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, 2017 से इन क्षेत्रों के अपने नाम जारी करता रहा है। भारत ने चीन के इस कदम को पूरी तरह से व्यर्थ बताया है।

विविध समाचार

रांची में पुलिस -छात्र झड़प के बाद 14 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर 3 मामले दर्ज

रांची २३/०८ (संवाददाता): झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को भर्ती परीक्षाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अज़्यर्थियों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। कोतवाली थाने में सरकारी काम में बाधा डालने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में 14 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस कार्रवाई और एक महिला की हिरासत को लेकर पुलिस प्रशासन पर कड़ा विरोध जताया है। रांची में पुलिस और नौकरी के इच्छुक अज़्यर्थियों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में शनिवार को 14 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ कम से कम तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये प्राथमिकी सरकारी कामकाज में कथित तौर पर बाधा डालने और पुलिस के साथ झड़प करने के आरोप में रांची के कोतवाली थाने में दर्ज की गईं। रांची के पुलिस अधीक्षक (सिटी) पारस राणा ने कहा, ''शुक्रवार को हुई झड़प के सिलसिले में कोतवाली थाने में 14 नामजद आरोपियों और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।''

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि तीन में से एक प्राथमिकी पुलिस ने कथित उपद्रवियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और निर्धारित मार्ग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि दो अन्य प्राथमिकी दो व्यक्तियों द्वारा दर्ज करायी गई हैं। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने आरोप लगाया कि एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) चलाने वाली महिला अमीषा प्रसाद को शुक्रवार के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुलिस ने हिरासत में लिया और कोतवाली थाने लायी।

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची की महापौर रोशनी खलखो, भाजपा विधायक सी. पी. सिंह और अन्य नेता कोतवाली थाने पहुंचे और करीब तीन घंटे तक वहां रहे। मरांडी ने कहा, ''यह झारखंड पुलिस की गुंडागर्दी का एक उदाहरण है। जिस तरह से पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, उससे साफ तौर पर लगता है कि उसे प्रताड़ित किया गया।सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस सरकार को पता होना चाहिए कि आप जितना आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही बुलंद होगी।'' मरांडी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को पुतला दहन जुलूस के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ झारखंड सरकार के ''गुंडों'' और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का व्यवहार किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया, ''अगर महिला के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज था, तो पुलिस को उसे नोटिस देना चाहिए था, न कि आंदोलन में शामिल होने के बाद उसे हिरासत में लेकर थाने लाना चाहिए था। पुलिस अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले रही है, जबकि झामुमो कार्यकर्ताओं को संरक्षण दे रही है।'' हालांकि, पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि महिला को शुक्रवार की झड़प के सिलसिले में हिरासत में नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा, ''हम उसे करीब दो महीने पहले सदर थाने में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में थाने लाए।'' अधिकारियों के अनुसार, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच शुक्रवार को रांची में झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाने की कोशिश की थी। 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच' के बैनर तले छात्र नेताओं ने राज्य सरकार पर नौकरी के इच्छुक अज़्यर्थियों को ''धोखा देने'' और ''विश्वासघात'' करने का आरोप लगाया है।

यह आरोप 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तथा जेएसएससी-सीजीएल के जरिए की गई नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कुछ अधिसूचनाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद लगाया गया। उच्च न्यायालय ने बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त किए गए अज़्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर शुक्रवार को रोक लगा दी। बृहस्पतिवार को अदालत ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर रोक लगाई थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी।

भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा हमला! वंदे मातरज़्को लेकर तुष्टिकरण का आरोप, कहा- संसद और संविधान से ऊपर नहीं सीडज़्ल्यूसी

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): भाजपा ने शनिवार को 'वंदे मातरज़्' को लेकर कांग्रेस पर ''तुष्टिकरण की राजनीति'' करने का आरोप लगाया और कहा कि कोई भी दल या व्यक्ति संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी के नवनियुक्तपदाधिकारियों की पहली बैठक में 'वंदे मातरज़्' को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमिति (सीडज़्ल्यूसी) द्वारा 1937 के अपने फैसले की पुनः पुष्टि किए जाने के कुछ दिन बाद आया है, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में गीत के केवल पहले दो अंतरे गाने की बात कही गई थी। भाजपा के प्रस्ताव में कांग्रेस के इस फैसले की निंदा की गई और कहा गया कि राजनीतिक लाभ या तुष्टिकरण के लिए राष्ट्रीय गीत के सज़्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि वह विपक्षी दल को राष्ट्रीय गीत को ''विभाजित'' करने या उसमें ''छेड़छाड़'' करने की अनुमति नहीं देगी। भाजपा ने कहा कि उसका प्रस्ताव कांग्रेस के रुख का सीधा जवाब है और पार्टी 'वंदे मातरज़्' की पूरी विरासत की रक्षा के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगी।भाजपा मुज़्यालय में संवाददाता सज़्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को खुद को या अपनी कार्यसमिति को संसद से बड़ा नहीं समझना चाहिए। पात्रा ने कहा, ''आज मैं देश से पूछना चाहता हूं कि संसद बड़ी है या सीडज़्ल्यूसी? देश संसद में लिए गए फैसलों के आधार पर चलेगा या सीडज़्ल्यूसी के फैसलों और प्रस्तावों के आधार पर?'' उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल, परिवार या व्यक्ति संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता।

पात्रा ने कहा, ''किसी परिवार, राजनीतिक दल या व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह देश के कानून, संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बड़ा है।'' उन्होंने कहा, ''कांग्रेस कार्यसमिति अपने कार्यालय में बैठकर खुद को संसद से बड़ा नहीं समझ सकती। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। संसद में लिया गया हर फैसला देश का फैसला होता है।''

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए 'वंदे मातरज़्' को लेकर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी इसके गायन में किसी भी तरह की बाधा डालने के प्रयास का विरोध करेगी। पात्रा ने कहा, ''वंदे मातरम् राष्ट्र का गीत है। यह राष्ट्र का मंत्र है। यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने का माध्यम नहीं है। कांग्रेस विभाजन के बीज बोने का प्रयास कर रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

आर्थिक आधार पर आरक्षण का मायावती ने किया कड़ा विरोध

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने जाति-आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग का विरोध किया और कहा कि ऐसा कदम देश के हित में नहीं होगा। उज़र प्रदेश की पूर्व मुज़्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान इन समुदायों को सदियों से झेल रहे भेदभाव और वंचना को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ मांग उठाने वालों को ऐसा कोई कदम उठाने से बचना चाहिए, जिससे समतामूलक

समाज और विकसित एवं गरिमापूर्ण राष्ट्र के निर्माण के संवैधानिक उद्देश्य को नुकसान पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के लिए जुटे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों को इस प्रदर्शन के लिए जुटाया गया था। उनकी मांग है कि सरकारी सहायता और आरक्षण की पात्रता तय करने में जाति के बजाय आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जाए।

इस मांग का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस का कोई अन्य नेता प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचा और न ही उन्हें अपनी पार्टी का रुख समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह इन समुदायों के प्रति कांग्रेस की 'आरक्षण विरोधी मानसिकता' को दर्शाता है। मायावती ने जातिवाद पर बी. आर. आंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि जातिवाद को छोड़ना ही ''सबसे बड़ा देशभक्ति का कार्य'' है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पहले से ही गरीबी दूर करने वाली कई योजनाओं पर बड़ी मात्रा में सरकारी धन खर्च कर रही हैं, लेकिन यदि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियों के कारण इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो यह सरकारी व्यवस्था की विफलता है।

उन्होंने कहा, ''देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण पहले से ही लागू है।'' बसपा प्रमुख ने कहा कि उच्च जाति के गरीब परिवारों को भी इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और यह व्यवस्था काफी हद तक अपर्याप्त साबित हुई है। मायावती ने आरोप लगाया कि 'भ्रष्ट और जातिवादी' सरकारी व्यवस्था ने आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू नहीं होने दिया।

उन्होंने दावा किया कि आजादी के दशकों बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग गरीबी, जातिगत भेदभाव, शोषण, अत्याचार और सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकारों से आरक्षण का विरोध करने वाले तत्वों को ''आश्रय या संरक्षण'' नहीं देने का आग्रह किया। साथ ही राजनीतिक दलों और लोगों से इस संवेदनशील मुद्दे पर ''सस्ती राजनीति'' नहीं करने की अपील की।

पीएम मोदी के निर्देश पर भाजपा का जेन जी मिशन, युवाओं को साधने की सियासी रणनीति

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी ने जेन % तक पहुँचने के अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक खास टीम बनाई है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस निर्देश के कुछ दिनों बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने मंत्रियों से कहा था कि वे सीधे बातचीत और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए युवाओं के साथ जुड़ाव मज़बूत करें। पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्र ने समाचार एजेंसी,हृ्ढ को बताया कि इस टीम में ङ्क्षछ्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी, छज़ीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी और कई अन्य नेता शामिल हैं।

युवा पीढ़ी के साथ ज़्यादा सीधा और लगातार संवाद बनाने की कोशिशों के तहत, बीजेपी जल्द ही %जेन ज़ेड% (त्वद्गठ्ठ) के साथ आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने वाली है। यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष ने भी युवा वोटरों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाया है; राहुल गांधी कई राज्यों में छात्रों की गूंज आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली में %कॉकरोच जनता पार्टी% (ष्टछ्वक्क) के नेतृत्व में हुए

विरोध-प्रदर्शनों के बाद, और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों को युवाओं से ज़्यादा जुड़ने के निर्देश देने के बाद, ङ्क्षछ्क ने %जेन % (त्वद्गठ्ठ) के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाया है।

इस आउटरीच प्रोग्राम से %जेन % की उज़्मीदों, चिंताओं और अपेक्षाओं को समझने की उज़्मीद है। साथ ही, यह युवाओं को ङ्क्षछ्क नेताओं से सीधे जुड़ने और कई मुद्दों पर अपनी राय रखने का मंच भी देगा। पार्टी इस पहल का इस्तेमाल युवा वोटरों के साथ अपना जुड़ाव मज़बूत करने और बातचीत, चर्चा व अन्य गतिविधियों के ज़रिए अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए भी करेगी। आज इससे पहले, पार्टी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल के बाद नबिन ने नए नियुक्त पदाधिकारियों के साथ पहली परिचय बैठक की। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और नई टीम एक साथ आए, ज़्योंकि ङ्क्षछ्क अपने राजनीतिक और संगठनात्मक रोडमैप पर काम कर रही थी।

इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष, कार्यक्रम प्रभारी विनोद तावड़े, राज्य बीजेपी अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और संगठन महासचिव शामिल हुए। इस बैठक के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारियों की नई टीम का काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया। बैठक से पहले राष्ट्रगीत %वंदे मातरम% के सभी छह पद गाए गए। बैठक में पुराने और नए, दोनों तरह के पदाधिकारी शामिल हुए और बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति और राजनीतिक रोडमैप पर चर्चा की गई।

आरक्षण खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार है-चिराग पासवान

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आरक्षण-विरोधी प्रदर्शनों पर अपनी राय रखी। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने और चीनी के बढ़ते दामों पर भी अपनी बात रखी।

पासवान ने कहा कि जंतर-मंतर पर जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग अगर अपनी मांगों को सुव्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखेंगे, तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसे किसी के मांगने से खत्म नहीं किया जा सकता। जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर उन्होंने साफ किया कि एनडीए सरकार पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है।

चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करके %वंदे मातरम% विवाद से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए करना गलत है। कांग्रेस नेतृत्व इस समय %वंदे मातरम% के अनादर से जुड़े सवालों से घिरा हुआ है।

पटना में छात्रों के प्रदर्शन को राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए समर्थन पर पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते यह उनकी जिज़्मेदारी के अनुरूप है और यह अच्छी बात है। देश में चीनी की कीमतों में हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या के जल्द समाधान पर काम कर रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के पीछे हालिया समय में देश में गर्माए कुछ प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं। हाल के महीनों में देश के विभिन्न राज्यों में जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा (50त्न की सीमा) बढ़ाने को लेकर मांगें तेज हुई हैं। इसके विरोध में एक तबका, विशेषकर गैर-आरक्षित वर्ग, सड़कों पर उतरा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का आधार %जाति% के बजाय केवल %आर्थिक स्थिति% होना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।

राहुल गांधी बोले सरकार से सवाल पूछने पर गालियां मिलीं पर मैं नहीं सुधरूंगा

नयी दिल्ली २३/०८ (संवाददाता): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सरकार को नापसंद मुद्दों पर सवाल उठाने के कारण उन्हें वर्षों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह 'सुधर नहीं रहे'' हैं। गांधी ने पुणे में पार्टी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायिका नेहा राठौर से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। नेहा राठौर सरकार की आलोचना करने वाले अपने व्यंग्यात्मक गीतों के लिए जानी जाती हैं। राठौर ने कहा कि वह महिलाओं के साथ होने वाले ''अनादर'' के बारे में बात करने आई हैं और सवाल किया कि अगर

महिलाएं सज़ा में बैठे लोगों से सवाल नहीं कर सकतीं, तो उन्हें किस तरह का सज़्मान मिलेगा। उन्होंने कहा, ''मैं सरकार को नापसंद आने वाले सभी मुद्दों पर सवाल उठाती हूं। इसके बदले मुझे काफी गालियां और प्राथमिकी झेलनी पड़ती हैं।

महिलाओं के प्रति यह कैसा सज़्मान है? अगर लोकतंत्र में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते, तो यह कैसा सज़्मान होगा?'' राठौर ने शादी के बाद उज़र प्रदेश में एक व्यंग्यात्मक गीत गाने की घटना को याद करते हुए कहा कि पुलिस की टीम उनके पीछे भेजी गई थी और इलाके के लोगों ने उनके परिवार से सवाल किया था कि वह किस तरह की महिला हैं। उन्होंने कहा, ''एक महिला के तौर पर अगर आप समाज के कुछ मुद्दों पर बोलना चाहती हैं, तो यह बहुत मुश्किल होता है।पुरुषों को भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन महिलाओं को बहुत अलग तरह से निशाना बनाया जाता है।

लोग सीधे उनके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं।'' राठौर ने कहा कि वह ''थोड़ी निडर और जिद्दी'' हैं और आलोचना से डरती नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''वे मुझसे कहते हैं कि वे पिछले पांच साल से मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सुधरी नहीं हूं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि मैं सुधरने वाली नहीं हूं।'' राठौर की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने कहा कि उन्हें भी वर्षों से गालियां दी जा रही हैं, लेकिन इससे वह विचलित नहीं होंगे। गांधी ने कहा कि सरकार को नापसंद मुद्दों पर सवाल उठाने के कारण उन्हें वर्षों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने जोर दिया वह ''सुधरने वाले नहीं हैं।'' गांधी ने राठौर की बात दोहराते हुए कहा, ''मुझे भी वर्षों से गालियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं भी सुधरने वाला नहीं हूं।'' उन्होंने कहा, ''मैं भी नहीं सुधर रहा हूं।

विविध समाचार

ज्वार, मक्का, बाजरा के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन

ज्वार

अर्गट या गूंदिया रोग

रोग के लक्षण

दानों के बाहरी भाग पर गाढ़ा, रंगहीन अथवा हल्का गुलाबी चिपचिपा स्राव बूंदो के रूप में जमा होता है। बाजरा व इसकेमस घास इस रोगकारक के अन्य परपोषी हैं।

रोकथाम - खेत के आसपास अन्य परपोषी पौधों को हटा दें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी घोलकर (0.2 प्रतिशत) छिड़काव करें।

कंडवा रोग

रोग के लक्षण - ज्वार की फसल में चार विभिन्न प्रकार के कंडवा रोग लगते हैं। इनका पता भुट्टा आने पर ही चलता है।

आवृत कंडवा में भुट्टा के सारे बीज प्रभावित होते हैं जो काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। अनावृत कंडवा में भी सारे बीज प्रभावित होकर गांठे बनती है- जिस पर हल्की सफेद रंग की परत होती है। दीर्घ कंडवा में भुट्टा के कुछ दाने संक्रमित होकर लम्बी बेलनाकार संरचनाएं बनती हैं। शीर्ष कंडवा में पूरा भुट्टा ही एक गांठ के रूप में बदल जाता है।

शीर्ष कंडवा

रोकथाम - खेत में रोगग्रस्त सिट्टे दिखाई देते ही कागज या कपड़े की थैली से इन्हें ढककर काट लें व जलाकर नष्ट कर दें। बीजों की खुबाई पूर्व थाइरम 4 ग्राम या कार्बोक्सिन 2 ग्राम/किलो बीज दर से उपचारित करें।

पत्ती धब्बा रोग

रोग के लक्षण - ज्वार पर ग्यारह प्रकार के विभिन्न पत्ती धब्बा रोगों का आक्रमण होता है। ये रोग देशी किस्मों पर व्यापकता से फैलते हैं। ये पर्ण अंगमारी, लाल धब्बा, जोनेट धब्बा, टारगेट धब्बा, कज्जलीधारी, भूरा धब्बा, खुरदरा धब्बा, डेऊक्सेलेरा पत्ती झुलसा प्रमुखता से है।

रोकथाम - ये रोग बीजोढ़ होते है साथ ही फसल अवशेषों में जीवित रहते है अतः रोगग्रस्त अवशेषों को इकट्ठा कर जला दें। रोगग्रस्त फसल के बीज बुआई के काम में न लें। रोगरोधी किस्में जैसे सीएसव्ही 10,15,17, सीएचएच 5,6,9,14 की बुवाई करें। चारे के लिए देशी किस्में बोयें । कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/किलो बीज की दर से उपचारित करें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 0.2 प्रतिशत का छिड़काव करें।

चारकोल तना सड़न रोग

रोग के लक्षण - इस रोग से तने के निचले भाग अथवा जड़ों पर पहले हल्के रंग के बाद में काले रंग के धब्बे बनते हैं तथा उसमें सड़न प्रारंभ हो जाती है। बहुधा इस प्रकार के पौधे झुण्डों में होते है तथा सूखकर गिर जाते है, इससे उपज में बहुत अधिक हानि होती है।

रोकथाम

यह रबी की ज्वार में नमी कम होने पर अधिक होता है, अतः नमी का मृदा में संरक्षण करें। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति हैक्टेयर पौधों की संख्या अधिक या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी किस्में जो दाना पकते समय हरी रहती हो बोनी चाहिए क्योंकि इनमें चारकोल तना सड़न नही आता है।

बाजरा

मृदुरोमिल आसिता रोग

रोग के लक्षण - प्रारंभ में निचली पत्तियों पर लम्बवत 3 मिमी. चौड़ी पीले रंग की धारियां समान्तर रूप में बनती है। बाद में ये धारियां भूरे रंग में परिवर्तित होती है व इन धारियों पर सफेद रंग की कवक दिखाई देती है। कुछ समय पश्चात ये लक्षण ऊपर की पत्तियों पर भी दिखाई देने लगते हैं। पौधे की प्रारंभिक अवस्था में रोग की तीव्रता अधिक हो जाए तो पौधे समय से पूर्व ही मर जाते है। इस रोग से 20 - 60 प्रतिशत तक हानि हो सकती है।

रोग कारक- यह बीज एवं मृदा जनित रोग है जो स्क्लेरोस्पोरा टर्सीकस नामक फफूंद द्वारा होता है।

रोकथाम - फसल के अवशेषों को इकट्ठा कर जलायें। फसल चक्र अपनायें। खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाकर समय-समय पर पानी की निकासी करें। रोग रोधी किस्में जैसे गंगा-2, तरुण, जवाहर, किसान इत्यादि लगायें। रेडोमिल 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करें। खड़ी फसल में रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही ताम्रयुक्त फफूंदनाशक ब्लाइटॉक्स -50 या फाइटोलान दवा 3 ग्राम 1 लीटर की दर से या रेडोमिल एम. 6 ग्राम / लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता को देखते हुए 10- 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव दुहरायें।

भूरी चित्ती रोग

रोग के लक्षण - पत्तियों, पर्णच्छेद, तने एवं भुट्टे के बाहरी छिलके पर हल्के पीले रंग के 1-5 मि.मी. व्यास के गोलाकार/ अंडाकार धब्बे बनते जाते हैं। तीव्र प्रकोप की अवस्था में धब्बे अधिक संख्या में बनते हैं और आपस में मिल जाते हैं। रोगग्रस्त भाग जंग लगा सा दिखाई देता है। तीव्र प्रकोप की अवस्था में पत्तियां विकसित हुए बिना ही सूख जाती है तथा धब्बे भुट्टों पर बन जाते हैं। अत्यधिक प्रकोप से उपज में 25 प्रतिशत तक हानि हो सकती है।

रोग कारक - यह बीज जनित रोग है जो पाइरोग्रा ओब्टिसा नामक फफूंद से होता है।

रोकथाम - खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। फसल चक्र अपनायें। बोने के पूर्व बीजों को थायरम या मैंकोजेब नामक फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम/किलो बीज की दर से उपचारित करें। रोग के प्रारंभिक लक्षण देखते ही ताम्रयुक्त फफूंदनाशक ब्लाइटॉक्स -50 या फाइटोलान दवा 3 ग्राम/ लीटर की दर से छिड़काव करें। रोग की तीव्रता को देखते हुए 10-15 दिनों के अंतराल में छिड़काव दुहरायें।

मक्का

टर्सीकस पर्ण अंगमारी रोग

रोग के लक्षण - अंकुरण के 4 - 5 सप्ताह के बाद इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते है। सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। लम्बे वृत्ताकार या नाव के आकार के भूसर हरे रंग के 15 से.मी. लम्बे व 3-4 से.मी. चौड़े होते हैं। तीव्र प्रकोप की अवस्था में पत्तियां पूरी तरह सूख जाती है एवं भुट्टे की संख्या एवं उपज में कमी आ जाती है। इस रोग के प्रकोप से उपज में 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

रोग कारक - यह मृदा जनित रोग है जो हेलमेन्थोस्पोरियम टर्सीकम नामक फफूंद द्वारा फैलता है।

रोकथाम - पहले के फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट करें। रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे गंगा - 21, एच- 216, जय किसान इत्यादि लगायें। बोने के पूर्व बीजों को थायरम फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम/किलो बीज की दर से उपचारित करें। खड़ी फसल पर प्रारंभिक लक्षण दिखते ही जाइनेब या मैंकोजेब दवा 3 ग्राम/लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता को देखते हुए 15 दिनों के अंतराल से छिड़काव करें। ताम्रयुक्त फफूंदनाशक ब्लाइटॉक्स -50 या फाइटोलान दवा 3 ग्राम/लीटर की दर से घोलकर छिड़काव करें।

सूरजमुखी में रोग निदान

मुख्य रोग एवं प्रबंधन

आल्टरनेरिया पत्ती धब्बा एवं झुलसा:

यह रोग आल्टरनेरिया हेलिएन्थाई नामक कवक से होता है। यह रोग सभी स्थानों पर भारी हानि करता है। यह खरीफ की सूरजमुखी फसल में मुख्य रोग है। संक्रमित बीजों की अंकुरण क्षमता में 23 से 32 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।

प्रबंधनः

- फसल के रोगग्रस्त अवशेषों को नष्ट करें।
- बीजों को आइप्रोडियोन 2 ग्राम प्रति किलो बीज से बीजोपचार तथा फसल पर आइप्रोडियॉन 0.2 प्रतिशत या प्रोपिकोनाजोल (टिल्ट) 0.1 प्रतिशत घोल का फसल पर 30 एवं 45 दिन पर छिड़काव करें।
- साफ एवं स्वस्थ बीजों को बोने के काम में लें।
- फसल चक्र अपनावें।

मृदुरोमिल आसिता (डाऊनी मिल्ड्यू)

यह रोग प्लाज्मापेरा हलस्टीकी नामक कवक से होता है। इस रोग की उग्रता प्रत्येक वर्ष में मौसम पर निर्भर है। इस रोग की सर्वांगिक (सिस्टेमिक) अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है। इससे 95 प्रतिशत तक हानि हो सकती है।

प्रबंधन

- पौधों के रोगी अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें क्योंकि इन्ही से रोग की शुरूआत होती है।
- भूमि में पड़े अवशेषों को नष्ट करने के लिए उसे 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिये।
- स्वस्थ एवं उपचारित बीज बोने के काम में लें।
- बीजोढ़ रोग को मेटालेक्सिल (एप्रान एस डी 35)
- 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर नष्ट करें।
- रोग रोधी हाइब्रिड बोएं जिन क्षेत्रों में रोग अधिक हो।

रोली या रतुआ (रस्ट)

यह रोग पक्सीनिया हेलिएन्थाई नामक कवक से होता है । यह रोग फसल रोपण के 30 दिनों बाद वातावरण में नमी के साथ यह गंभीर हो जाता है। इसके प्रकोप से बीज की पैदावार एवं तेल की मात्रा में कमी आती है।

प्रबंधन

- फसल चक्र अपनावें
- रोगग्रस्त अवशेषों एवं खाली खेतों में खड़े पौधों को नष्ट कर देना चाहिये।
- रोग के लक्षण दिखाई देते ही मेन्कोजेब 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिये। छिड़काव पत्तियों की निचली सतह तक करें।

मूल विगलन

यह रोग फसल की किसी भी अवस्था में देखा जा सकता है। भारत में इस रोग से 30 से 45 प्रतिशत तक की क्षति आंकी गई है। यह रोग मेक्रोफोमिना फैजियोलिना नामक कवक से होता है। शुष्क एवं भूमि में नमी की कमी में खरीफ की फसल में अधिक होता है।

प्रबंधन

- फसल चक्र अपनाना चाहिए।
- एक की खेत में सूरजमुखी की फसल लगातार नहीं लेनी चाहिए।
- कार्बेण्डाजिम कवकनाशी से बीजोपचार करना चाहिए।
- भूमि में जल निकास अच्छा होना चाहिए।

कॉलर विगलन (कॉलर रॉट):

यह रोग स्क्लेरोशियम रोलफ्साई नामक कवक से होता है। यह रोग विश्व में बहुत सारे देशों में महत्वपूर्ण है। यह रोग खरीफ की फसल में शुष्क एवं नमी की कमी में अधिक होता है।

प्रबंधन

- ऊपर मूल विगलन रोग की रोकथाम की तरह ही फसल चक्र, बीजोपचार एवं अच्छे जल निकास वाली भूमि चुनाव करके इस रोग का नियंत्रण करें।

नेक्रोसिस डिसिज

पिछले कुछ वर्षों में सनफ्लावर नेक्रोसिस डिसिज एक मुख्य विषाणु रोग सूरजमुखी उगाने वाले क्षेत्रों में समस्या है। यह रोग एक विषाणु टोबेको स्ट्रीक वायरस से होता है। यह रोग खरीफ एवं रबी दोनों ही फसलों में होता है। इससे शत-प्रतिशत नुकसान होता है।

प्रबंधनः

- सूरजमुखी फसल के चारों ओर किनारों (बॉर्डर) पर तेजी से बढ़ने वाली फसलें जिसमें मक्का, बाजरा, ज्वार लगावें जिससे कि वायरस फैलाने वाले थ्रिप्स का विचरण रूक जाय जो कि नेक्रोसिस रोग फैलाते है।
- रोग नियंत्रण हेतु बीजोपचार थायोमिथोक्साम (क्रूजर) 4 ग्राम प्रति किलो बीज से तथा फसल पर थाथामिथाक्साम 0.05 प्रतिशत घोल का 30 से 45 दिन पर छिड़काव करें।

पाउडरी मिल्ड्यू

यह रोग इरीसायफी सिकोईसियम नामक कवक से होता है। यह रोग खरी की फसल में अधिक होता है तथा शुष्क मौसम में होता है।

प्रबंधन

- रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही फसल पर 0.2 प्रतिशत गंधक या गंधक चूर्ण 25 कि./हेक्टर या केराथेन 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए।
- रोग नियंत्रण हेतु बेनलोट 0.05 प्रतिशत भी उपयोगी हैं।

शीर्ष विगलन (हेड रोट)

जिन वर्षों में शीर्ष बनने की अवस्था पर अधिक वर्षा हो या रूक-रूक कर बौछारें आती हो तो यह रोग ज्यादा होता है। यह रोग खरीफ की फसल में अधिक होता है। इस रोग से पूरे शीर्ष का विगलन होकर काफी हानि होती है।

प्रबंधन

- स्वस्थ, स्वच्छ एवं उपचारित बीज बोने के काम में लें।
- खेतों को साफ रखें। पौधों का मलबा खेत में न रखें।
- कवकनाशी मेन्कोजेब 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें। यह छिड़काव शीर्षांग बनने के समय करें।

कलिंग समाचार

संपादकीय

मोदी की विदेश नीति पर सवालिया निशान

नरेन्द्र मोदी सरकार जिस विदेश नीति पर चल रही है, उसके संभावित नुकसान के बारे में राहुल गांधी काफी पहले से आगाह करते रहे हैं। लेकिन कभी भी नेता प्रतिपक्ष श्री गांधी की सही सलाह को मोदी सरकार ने नहीं सुना, बल्कि भाजपा नेता उन्हें राजनीति का नौसिखिया साबित करने में लगे रहे या फिर उनके बयानों से देशविरोधी ताकतों को बल मिलता है, ये आरोप लगाते रहे। अभी डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम के दावों को लेकर भी राहुल गांधी ने जो सवाल किए उसके बाद भाजपा नेताओं ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें निशान-ए-पाकिस्तान से नवाज़ा जाएगा। घरेलू राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन विदेश नीति में सारे दल अब तक एकजुटता दिखाते रहे हैं, मगर अब मोदी सरकार में यह परंपरा भी टूट चुकी है। अब विदेश नीति मोदीनीति के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 33 देशों में भेजा गया सर्वदलीय प्रतिनिधमंडल इसकी मिसाल है। भारत के पहले भी पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध हुए, कभी भी भारत ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि परिस्थितियां संभालने के लिए उसे हथियार उठाने पड़े। यह बात पूरी दुनिया में अकाट्य सत्य की तरह बनी हुई है, इसलिए इससे पहले भारत को कभी भी अपना पक्ष रखने के लिए सांसदों, राजनयिकों की टोली देश-देश नहीं भेजनी पड़ी। इस बार भी भारत ऐसा कुछ न करता तब भी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं करती। क्योंकि जैसा हमेशा हुआ, अब भी वैसा ही हुआ कि सीमापार से आतंकी हमारी धरती पर आए, हमला किया, निर्दोष नागरिकों को मारा और तब जाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान ने पलटवार करने के लिए जो कदम उठाए, भारत ने उनका भी तगड़ा जवाब दिया। अफसोस है कि पुंछ जैसे सीमाई इलाकों में निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, लेकिन यहां सेना की नहीं सरकार की गलती थी, कि उसने पहले से नागरिक सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। बाकी जिन शहरों या सैन्य अड्डों को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, वो सारी हमारी रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दी थी। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दिया। ट्रंप की मध्यस्थता से भारत युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ यह संदेश तो पूरी दुनिया में गया ही, क्योंकि भारत ने अब तक इसका खंडन नहीं किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी बढ़कर बोलने और खुद को पीड़ित की तरह पेश करने का मौका मिला। मोदी सरकार की विदेश नीति की यह सबसे बड़ी असफलता थी कि जिन देशों ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत के लिए सहानुभूति दिखाई, उनमें से कोई ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत के साथ खड़ा नहीं रहा, अफगानिस्तान को छोड़कर। अब प्रधानमंत्री मोदी देश में तो खुद घूम-घूमकर ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने और उस पर राजनीति करने में लगे हैं, उधर उनका पक्ष रखने के लिए विदेशों में गया प्रतिनिधिमंडल भी भारत के पक्ष में माहौल बनाने में किस हद तक सफल होगा, यह विचारणीय है। क्योंकि इन प्रतिनिधिमंडलों की बैठकें अमूमन सामाजिक संगठनों, विचार मंचों, और वहां के प्रवासी भारतीय समुदाय से हो रही हैं, बहुत कम देशों में सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक इन दलों की हुई है। जबकि विदेश नीति के मसले, किस देश को किस मुद्दे पर कितना साथ देना है, ऐसे फैसले सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही तय करते हैं, जो नीति निर्धारक होते हैं असल शक्ति उनके हाथों में होती है, और इन लोगों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठकें हुई हैं, ऐसा देखने नहीं मिला। मेहमाननवाजी के तकाजे के हिसाब से अपने देश आए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को हर देश स मान दे रहा है, उनकी बात सुन रहा है, आतंकवाद की निंदा भी कर रहा है, लेकिन क्या मोदी सरकार का मकसद केवल यही था। अगर ऐसा ही समर्थन जुटाना था तो फिर इन तमाम देशों में भारतीय दूतावास इस जि मेदारी को पूरा कर सकते थे। अच्छी, मनलुभावन बातें करने के लिए क्या जनता के धन पर इन प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया है।

छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया

राजेश पांडेय

शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से है। असंतोष और संकट के मूल में बढ़ती बेरोजगारी है। हर साल वर्क फोर्स में 70-80 लाख युवा जुड़ते हैं। 80प्रतिशत बेरोजगार 15 से 24 आयु वर्ग के हैं। ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 29 फीसदी के आसपास है। आंदोलनों की अगली कतार में इस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। स्कूली छात्रों के जुड़ने का कारण अनिश्चित भविष्य तो है ही। 20 जून को जंतर-मंतर, नई दिल्ली से शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की आवाज देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश,राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और रैलियां निकाली हैं। कहीं बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी, तो कहीं होस्टल की ज्यादा फीस जैसे मुद्दों ने छात्रों को सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। बदलाव और बेचैनी की ऊर्जा से भरी यह हलचल हमारे समाज, राजनीति और सरकारी तंत्र को वर्तमान दौर की चुनौतियों को समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देती है।

इन आंदोलनों ने कुछ अहम पहलुओं को रेखांकित किया है। कुछ नए ट्रेंड उभर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। आमतौर पर किसी मुद्दे, मांग या विषय के पक्ष-विपक्ष में जनता के विभिन्न वर्ग बड़े शहरों में एकजुट होते आए हैं। अक्सर राजनीतिक दलों, छात्रों, मजदूर संघों और सामाजिक संगठनों द्वारा जनमत जगाने, विरोध जताने और लोगों को संगठित करने की मुहिम राजधानियों या बड़े शहरों में आकार लेती है। बहुत व्यापक आंदोलनों को छोड़ दें तो कई बार वह उन्हीं स्थानों तक सिमटकर रह जाती है। इस बार स्थिति अलग है। दिल्ली, भोपाल, रायपुर जैसी राजधानियों से उठी आवाज की अनुगूंज छोटे शहरों में सुनाई पड़ रही है।

आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों के स्वरूप में हुआ है। कॉलेज छात्रों के साथ स्कूली छात्र आगे आए हैं। स्कूली छात्र सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित नहीं हैं। कई जगह मिडिल स्कूल के छात्रों ने सीनियर साथियों के साथ मोर्चा संभाला है। लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। वे सिर्फ दिल्ली या राजधानियों में ही नहीं छोटे शहरों तक में सड़क पर उतरी हैं। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर है, वे मौजूदा स्थितियों में अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें जिंदगी की दौड़ में पिछड़ने का खतरा नजर आता होगा।

छोटे शहरों के छात्रों के जागरूक होने का मु य कारण उनकी मांग तो है ही पर सोशल मीडिया ने उनके लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मोबाइल के परदे का छोटा स्क्रीन उन्हें दिल्ली से लेकर सैनफ्रांसिस्को तक की हलचल की जानकारी देता है। वे सिर्फ रील बनाने, देखने या मनोरंजन तक सीमित नहीं होंगे। उन्हें साइंस, टेक्नालॉजी, इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। स्पेस साइंस के चमत्कार भी उनकी कल्पनाओं का हिस्सा बन रहे होंगे। वे देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के कोई मार्क जकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा टूल बनाते हैं तो कैसे ओपन एआई के सैम आल्टमैन चैट जीपीटी पेश कर रहे हैं। वे यह भी जानने लगे हैं किस तरह मेडिकल साइंस ने दिल और मस्तिष्क के रोगों सहित कई लाइलाज बीमारियों में राहत देने का रास्ता खोज लिया है।

सूचना क्रांति का वर्तमान समय छात्रों सहित हर किसी को लोकतंत्र, आजादी और खुलेपन की अहमियत बताता है। वह उनके अंदर सिस्टम की जड़ता को तोड़ने और नई राह पर चलने की बेचैनी पैदा करता है। उन्हें कहीं लगता है कि वे असली बदलाव से बहुत दूर हैं। युवा महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था उन्हें सिर्फ प्रतियोगिता की अंतहीन होड़ में झोंक रही है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक

संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा राज्यों का विषय है। इसलिए राज्यों के हिस्से में शिक्षा के खर्च का हिस्सा 75 प्रतिशत और केंद्र सरकार का 25 प्रतिशत है। प्रचार अभियान और चुनाव शिक्षा की पहली सीढ़ी स्कूल हैं। इसलिए उसके खर्च में कमी का असर भविष्य में शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर पर पड़ता है। अपर्याप्त बजट का नतीजा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शाला भवनों की दुर्दशा और अन्य सुविधाओं के अभाव में सामने आया है। विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के स्कूल ज्यादा अभावग्रस्त हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उपेक्षा को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं।

व्यवस्था को नैतिकता, ईमानदारी, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्यों के प्रसार का वाहक होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। हम हर कहीं मूल्यों का क्षरण देखते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है। ऐसे सिस्टम से युवाओं का मोहभंग और हताशा स्वाभाविक है। आधुनिक दौर में ऐसी व्यवस्था के खिलाफ ताकतवर स्वर उभरते रहे हैं। युवाओं और आम लोगों ने समय-समय पर सत्ता को झकझोरने के लिए अपना असंतोष जाहिर किया है। छात्रों के सत्याग्रह का जिक्र होता है तो मार्च, मई 1968 में फ्रांस के छात्र आंदोलन को हमेशा याद किया जाता है। उस वक्त पेरिस में छात्रों ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्रों की भीड़, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त साधनों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। देश की ट्रेड यूनियन भी छात्रों के साथ खड़ी हो गई थीं। आंदोलन दूसरे शहरों में फैल गया। मजदूर संघों के साथ आने से कारखानों, द तरों में काम ठप पड़ गया था। फ्रांस के आंदोलन में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल की दस साल लंबी सत्ता का विरोध भी जुड़ा था। डिगाल का शासन अनुदारवादी था। उनकी तानाशाही और मनमानी के खिलाफ नौजवानों और मजदूर वर्ग में असंतोष पनप रहा था। डिगाल ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने नेशनल असे बली भंग कर दी। नए चुनाव कराए। देश में फैली अस्थिरता से परेशान मध्यम वर्ग ने डिगाल का समर्थन किया। उनकी पार्टी को संसद में फिर बहुमत मिल गया। 1969 में डिगाल ने संसद के स्वरूप में बदलाव के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया। लेकिन जनमतसंग्रह में हारने पर अप्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ज़्यादा जानें अर्थजगत समाचार विशेष रिपोर्ट विदेश समाचार भारत में विभिन्न स्तरों पर चल रही छात्रों की हलचल का संबंध व्यवस्था विरोधी भी है। निश्चित रूप से वह स्कूल, कॉलेजों में साधनों के अभाव से जुड़ा है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.8 से 4.3 प्रतिशत के बीच चल रहा है। वैसे, राष्ट्रीय नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की नीति रही है। लेकिन सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा राज्यों का विषय है। इसलिए राज्यों के हिस्से में शिक्षा के खर्च का हिस्सा 75 प्रतिशत और केंद्र सरकार का 25 प्रतिशत है। प्रचार अभियान और चुनाव शिक्षा की पहली सीढ़ी स्कूल हैं। इसलिए उसके खर्च में कमी का असर भविष्य में शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर पर पड़ता है। अपर्याप्त बजट का नतीजा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शाला भवनों की दुर्दशा और अन्य सुविधाओं के अभाव में सामने आया है। विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के स्कूल ज्यादा अभावग्रस्त हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उपेक्षा को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं। देश में 2014-15 से 2024-25 के बीच सरकारी स्कूलों की सं या 94 हजार कम हुई है। इसमें उन स्कूलों की सं या शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारें किसी अन्य स्कूल में शामिल करती हैं।

अच्छी बात यह है कि इस दर यान शिक्षकों की सं या में 11 लाख से अधिक इजाफा हुआ है। इन स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की सं या दो करोड़ 26 लाख कम हो गई थी। सरकारी स्कूलों की घटती सं या और साधनों का अभाव शिक्षा के प्रति सरकारों की प्राथमिकता का प्रमाण है। रोजगार के नए अवसरों के सृजन और भावी चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने के मामले में भी सरकारी तंत्र की भूमिका कारगर नहीं है। ज़्यादा जानें राज्य समाचार खेल जगत अपडेट संपादकीय आलेख भारत में शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से है। असंतोष और संकट के मूल में बढ़ती बेरोजगारी है। हर साल वर्क फोर्स में 70-80 लाख युवा जुड़ते हैं। 80प्रतिशत बेरोजगार 15 से 24 आयु वर्ग के हैं। ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 29 फीसदी के आसपास है। आंदोलनों की अगली कतार में इस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। स्कूली छात्रों के जुड़ने का कारण अनिश्चित भविष्य तो है ही। वे महसूस कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी किसी अच्छी नौकरी के आसार बहुत कम हैं। अपने स्कूल की असुविधा, शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं उनके गुस्से के लिए चिन्गारी पैदा करती हैं। भारत समाचार छात्रों के आंदोलन के कुछ फौरी नतीजे निकले हैं। 26 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे ने जंतर-मंतर पर छात्रों का धरना समाप्त करा दिया। झारखंड सरकार ने 19 अगस्त को 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। रांची में छात्र आंदोलन के दबाव में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीआईडी जांच कराने का फैसला किया गया है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर सरकारें, प्रशासन और स्कूलों ने छात्रों की कुछ मांगें पूरी की हैं। लेकिन ऐसे फैसले अस्थायी राहत देते हैं। इनमें लंबी अवधि की कोई ठोस रणनीति और सुविचारित योजना नजर नहीं आती है। महज भाषणों, वादों और सोशल मीडिया रील्स से उन्हें लंबे समय तक भरमाए नहीं रखा जा सकता है। छात्रों को 21 वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने का सिलसिला स्कूलों से शुरू होना चाहिए। उन्हें वर्तमान टेक्नालॉजी, जॉब मार्केट और कॉरपोरेट सेक्टर की जरूरतों के हिसाब से गढ़ा जाए।

पीएम केयर्स फंड का ऑडिट

डॉ. ज्ञान पाठक

आलोचनाओं में से एक यह थी कि जो फंड जनता का पैसा स्वीकार करता है- जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योगदान और दूसरों से दान शामिल है - उसे पब्लिक ऑडिट के दायरे से बाहर क्यों रखा जाए, जबकि इस निजी फंड को एक सरकारी संस्था जैसा दिखाया जाता है। आलोचकों का तर्क था कि यह बेईमानी थी। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मार्च 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद %पीएम केयर्स% नाम का प्रचार-प्रसार वाला शब्द गढ़ा था, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वह लोगों का ध्यान रखते हैं। इस शब्दावली को विस्तारित कर इसका नाम रखा गया %प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन एसिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन% (आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत) रखा गया और इसे 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया, ठीक 24 मार्च 2020 की शाम को लॉकडाउन की घोषणा के बाद। विपक्ष का आरोप था कि इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग इसलिए बनाया गया था ताकि फंड की सार्वजनिक जांच से बचा जा सके। अब छह साल बाद हमें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय दान का पैसा बैंकों में फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखना ज़्यादा पसंद था।

इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब 2024-25 के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक किया गया। ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान पीएम केयर्स फंड को कुल 1279.9 करोड़ रुपये मिले, लेकिन उसने केवल 87.85 लाख रुपये खर्च किए। पीएम केयर्स फंड के पास कुल 8,542 करोड़ रुपये उपलब्ध थे, जिसमें से 7,847 करोड़ रुपये (लगभग 93 प्रतिशत) बैंकों में फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखे गए थे, जबकि 605 करोड़ रुपये सेविंग्स अकाउंट में रखे गए थे। यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को दर्शाता है, जिन्होंने देश के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही लगती है।

जब से पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई, यह मु य रूप से एक ट्रस्ट के तहत निजी फंड के रूप में स्थापित होने के कारण विवादों में रहा, हालांकि इसमें राष्ट्रीय प्रतीक %सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ% का इस्तेमाल किया गया था, जिसके आधार पर %सत्यमेव जयते% लिखा था और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी शामिल था। ऐसा स्पष्ट रूप से कैग ऑडिट से बचने और आरटीआई अधिनियम के तहत जनता को जानकारी देने से रोकने के लिए किया गया था। इसे एक सरकारी संस्था के तौर पर नहीं बनाया गया था, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर दान मांगा और लिया गया था। जमा किए गए फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और फंड के ट्रस्टी अपनी मज़ी से करते हैं, और यह भारत सरकार के खातों का हिस्सा नहीं होता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय नियमित रूप से मिले फंड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं देता है। शुरुआती सालों से लेकर 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट बहुत देरी से जारी की गईं, और दो साल के अंतराल के बाद, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के ऑडिट किए गए स्टेटमेंट 18 अगस्त, 2026 को सार्वजनिक किए गए। यह फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है, और 2022-23 के दो वर्ष बाद भी पब्लिक ऑडिट स्टेटमेंट न होने के कारण इसे जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा।

आलोचनाओं में से एक यह थी कि जो फंड जनता का पैसा स्वीकार करता है- जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योगदान और दूसरों से दान शामिल है - उसे पब्लिक ऑडिट के दायरे से बाहर क्यों रखा जाए, जबकि इस निजी फंड को एक सरकारी संस्था जैसा दिखाया जाता है। आलोचकों का तर्क था कि यह बेईमानी थी। एक और विवाद प्रधानमंत्री के इस फंड के चेयरमैन (पदेन हैसियत से) होने और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के इसके ट्रस्टी होने से जुड़ा था। पीएम केयर्स ने हमेशा यही रुख अपनाया और आरटीआई आवेदकों को जानकारी देने से इनकार किया, यह कहते हुए कि ट्रस्ट आरटीआई एक्ट के तहत कोई सरकारी संस्था नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल दान लेने के लिए किया गया, जिसके लिए कानूनों में भी बदलाव किए गए- जैसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के नियमों में- और वह भी पिछली तारीख से लागू होने वाले बदलाव। इसकी आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि इसकी गतिविधियां जनता के प्रति जवाबदेही से परे थीं, और ये पूरी तरह से इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मज़ी (चाहे वह सही हो या गलत) पर निर्भर थीं। 2020-21 में पीएम केयर्स की कुल आय 7,913.5 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसने केवल 3,976.2 करोड़ रुपये खर्च किए। 2021-22 में फंड को 2,116.2 करोड़ रुपये मिले और उसने 3,716.3 करोड़ रुपये खर्च किए। 2022-23 में इसे 1,305.9 करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ 437.9 करोड़ रुपये खर्च किए; 2023-24 में इसे 904.9 करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ़ 15.6 करोड़ रुपये खर्च किए; और 2024-25 में इसे 1,279.9 करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ 0.9 करोड़ रुपये खर्च किए। कुल मिलाकर, मार्च 2020 में शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2025 तक, इस फंड ने अपनी कुल कमाई का पांचवें हिस्से से भी कम- यानी सिर्फ 18.4 प्रतिशत - खर्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसने अपने क्लोजिंग फंड का सिर्फ़ 0.01 प्रतिशत खर्च किया। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि फंड का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, जबकि बड़ी सं या में लोग प्राकृतिक और इंसानी आपदाओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में ज़रूरतमंदों की मदद के नाम पर मिले फंड का 93 प्रतिशत बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा करना नैतिक या मानवीय रूप से सही नहीं लगता।

इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों की कितनी परवाह करते हैं और बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के नाम पर बैंक डिपॉजिट बढ़ाने में उनकी कितनी दिलचस्पी है।

विविध समाचार

निर्माण श्रमिक पंजीकरण पोर्टल फिर शुरू पात्र श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ : अनिल विज

चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए निर्माण श्रमिक पंजीकरण पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया है। श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि लंबे समय से लंबित श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है, ताकि वास्तविक और पात्र श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना और व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पूर्व में मिली शिकायतों और अनियमितताओं की जांच के बाद संशोधित एवं अधिक मजबूत व्यवस्था के साथ पंजीकरण प्रक्रिया फिर शुरू की गई है। अनिल विज ने कहा कि नए निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। साथ ही, सत्यापन और जांच में पात्र पाए गए श्रमिकों की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया भी पुनः शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में जांच के दौरान पंजीकरण अमान्य या अपात्र पाया गया था, उनके लिए क्षेत्रीय

अधिकारियों की शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। प्रभावित श्रमिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति के समक्ष अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत से आधारभूत ढांचे तथा विकास परियोजनाओं को गति मिलती है। इसलिए सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करवाकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और हर सुविधा सही व्यक्ति तक पहुंचे।

कर्णप्रयाग घटना की निष्पक्ष जांच हो, सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे उत्तराखंड सरकार : जत्थेदार गड़गज्ज

अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सिख युवकों के साथ कथित दुर्व्यवहार और कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंट साहिब यात्रा पर जाने वाली संगत को किसी भी प्रकार की परेशानी या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। जत्थेदार गड़गज्ज ने गुरुवार को कहा कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किरपान छोड़कर यात्रा पर आने की सलाह देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट प्रबंधन से इस संबंध में जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले ट्रस्ट का दायित्व है कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि किसी भी सिख श्रद्धालु के साथ स्थानीय स्तर पर दुर्व्यवहार न हो। कर्णप्रयाग में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए जत्थेदार ने उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई को एकतरफा और निंदनीय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क विवाद के एक मामले में सिख युवकों पर गंभीर धाराएं लगाई गयीं, हिरासत में प्रताड़ित किया गया और सार्वजनिक रूप से उनकी पगड़ियां उतारकर घुमाया गया, जिससे सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थानीय लोगों ने सिख युवकों पर हमला किया था, जिसके बाद उन्होंने आत्मरक्षा में किरपान का प्रयोग किया। ऐसे में पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जत्थेदार ने कहा कि पगड़ी और किरपान सिख धर्म के पांच ककारों का हिस्सा हैं और गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक रूप से पगड़ी उतरवाना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारें और पुलिस प्रशासन सिख धार्मिक प्रतीकों के महत्व से भली–भांति परिचित हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में सिखों के खिलाफ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न और भेदभाव तुरंत रोका जाए। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ भड़काऊ तत्वों के दबाव में पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि सिख समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे सांप्रदायिक और भड़काऊ संदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जत्थेदार गड़गज्ज ने कहा कि ऐसी घटनाएं सिख समुदाय में अलगाव की भावना को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि हाल के समय में हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन सिखों के हित में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से हेमकुंट साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे "तैयार–बर–तैयार" और शस्त्रधारी स्वरूप में, लेकिन कानून और मर्यादा का पालन करते हुए यात्रा करें। उन्होंने युवाओं को उकसावे में न आने और कानून अपने हाथ में न लेने की सलाह दी। जत्थेदार ने उत्तराखंड स्थित सिख संगठनों को भी संगठित होकर श्रद्धालुओं की सहायता करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसजीपीसी को कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार सिख युवकों को पूर्ण कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने अपील की कि यदि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में किसी भी सिख श्रद्धालु के साथ कोई परेशानी होती है तो इसकी सूचना तुरंत श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय को दी जाये।

महिला संघ एडवा ने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की

शिमला। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एडवा) की हिमाचल प्रदेश इकाई ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। संघ की राज्य अध्यक्ष रंजना जारेट और राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने गुरुवार को एक साझा बयान जारी कर राज्य के अलग–अलग हिस्सों से सामने आयी महिलाओं की हत्या की हालिया घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों ने शिमला जिले में एक ही हफ्ते के भीतर हुई दो अलग–अलग घटनाओं का जिक्र किया। इनमें रोहडू में एक महिला की गोली मारकर की गयी हत्या और एक बुजुर्ग महिला का गला घोंटने का मामला शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं ने महिलाओं के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। महिला संगठन ने मंडी, कांगड़ा, सरकाघाट, कुल्लू और सैंज सहित विभिन्न जिलों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के हालिया मामलों का भी हवाला दिया और कहा कि इन दुखद घटनाओं के जख्म अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। संघ के अनुसार, ऐसे अपराधों का बार–बार होना एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है, जिस पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला संगठन की नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला कल्याण को लेकर राज्य सरकार के दावे जमीनी स्तर पर सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हत्या, यौन उत्पीड़न, अपहरण और प्रताड़ना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों को उजागर करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए संघ ने दावा किया कि साल 2026 में अब तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 478 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 49 मामले नाबालिगों के साथ यौन अपराधों से जुड़े यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज किए गए हैं। संगठन ने यह भी दावा किया कि इस अवधि के दौरान छेड़छाड़ के 117 और महिलाओं के अपहरण के लगभग 110 मामले भी दर्ज किए गए हैं। संघ ने आरोप लगाया कि घरेलू हिंसा और क्रूरता के कई मामले अक्सर दर्ज ही नहीं हो पाते या स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिए जाते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता और इस तरह की हिंसा की असली तस्वीर सामने नहीं आ पाती।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए संघ ने राज्य सरकार से मामलों की तेजी से जांच करने और आरोपियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने की अपील की है। संगठन ने सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने और राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

बड़ी सफलता : खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के दो वांटेड सदस्य मलेशिया से डिपोर्ट, पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार

चंडीगढ। पंजाब पुलिस ने खुफिया पर धमाके की कोशिश के लिए जिम्मेदार जानकारी पर आधारित एक बड़े ऑपरेशन में प्रतिबंधित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) से जुड़े दो वांटेड सदस्यों को मलेशिया से डिपोर्ट कराया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और रॉयल मलेशिया पुलिस (आरएमपी) के सहयोग से यह सफलता हासिल की। पंजाब के डीजीपी ने यह जानकारी दी। पंजाब डीजीपी ने बताया कि आरोपियों को पंजाब पुलिस ने नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया और आगे की जांच के लिए राज्य में ले आई। डीजीपी के अनुसार, आरोपियों की पहचान अंबाला के गुरविंदर सिंह और पटियाला के मंजीत सिंह के रूप में हुई। ये दोनों आरोपी मलेशिया में मौजूद केजेडएफ–समर्थित टेरर मॉड्यूल के अहम सदस्य थे। यह मॉड्यूल पंजाब में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइनों समेत रेलवे के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में शामिल था। इससे पहले, पंजाब पुलिस ने उस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जो 23 जनवरी को फतेहगढ़ साहिब के सिरहिंद के पास रेलवे फ्रेट कॉरिडोर लाइन पर हुए आईईडी ब्लास्ट और 27 अप्रैल को पटियाला जिले के शंभू के पास उसी कॉरिडोर था। जांच के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे, जिसमें आरपीजी लॉन्चर, आईईडी, आरडीएक्स, हैंड ग्रेनेड और गोला–बारूद के साथ हाई–एंड पिस्तौलें शामिल थीं। इस अंतरराष्ट्रीय साजिश की आगे की जांच में मलेशिया से काम कर रहे केजेडएफ हैंडलर्स और फंडिंग ऑपरेटर की भूमिका का पता चला। डिपोर्ट किए गए आरोपी पंजाब में केजेडएफ ऑपरेटिव्स तक ऑफशोर खातों के जरिए फंड पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे थे, जिससे राज्य में आतंकी हमलों को अंजाम देने और शांति व कानून–व्यवस्था बिगाड़ने की योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा था। डीजीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को पटियाला की अदालत में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस बड़े नेटवर्क का पता लगाने और साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस आतंकवादी के नेटवर्क को खत्म करने, फंडिंग रोकने और पंजाब की शांति, सुरक्षा व सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

लगभग 100 वर्षों बाद पुनर्जीवित हुआ ऐतिहासिक कादियां–ब्यास रेल परियोजना : श्री रवनीत सिंह बिट्टू

चंडीगढ़/गुरदासपुर। पंजाब के माझा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत सरकार ने लंबे समय से लंबित कादियांदृब्यास नई रेल लाइन परियोजना को पुनर्जीवित कर दिया है। आज रेल भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। कादियां ब्यास रेल लिंक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रस्तावित रेल लाइन गुरदासपुर जिले के कादियां को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ेगी। लगभग 39.68 किलोमीटर लंबी इस ब्रॉडगेज रेल लाइन की अनुमानित लागत करीब घ1,400 करोड़ है। इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तरी रेलवे द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित रेल मार्ग कादियां, धपाई, घुमान, बुटाला, सठियाला और ब्यास जैसे महत्वपूर्ण कस्बों एवं गांवों से होकर गुजरेगा। इससे माझा क्षेत्र के अनेक इलाकों को पहली बार रेल नेटवर्क से सीधा जुड़ाव मिलेगा तथा स्थानीय लोगों की आवाजाही और परिवहन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक रेलवे अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसमें घुमान और बुटाला में दो क्रॉसिंग स्टेशन, 11 प्रमुख पुल, 121 लघु पुल, 54 रोड अंडर ब्रिज, आधुनिक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार प्रणाली तथा भारत की स्वदेशी ट्रेन टक्कर–रोधी प्रणाली 'कवच' का प्रावधान शामिल है। परियोजना के इतिहास का उल्लेख करते हुए श्री बिट्टू ने कहा कि कादियांदृब्यास रेल लिंक की परिकल्पना ब्रिटिश काल में की गई थी। वर्ष 1928दृ29 में तत्कालीन नॉर्थ–वेस्टर्न रेलवे द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी तथा 1930 के दशक के प्रारंभ तक निर्माण कार्य का एक बड़ा हिस्सा पूरा भी कर लिया गया था। हालांकि बाद में बदलती परिस्थितियों और विकास प्राथमिकताओं के कारण यह परियोजना बंद कर दी गई। उन्होंने बताया कि परियोजना के रणनीतिक एवं विकासात्मक महत्व को देखते हुए इसे बाद में सामाजिक रूप से वांछनीय रेल संपर्क परियोजना के रूप में पुनर्जीवित किया गया तथा वर्ष 2010दृ11 के पूरक रेल बजट में शामिल किया गया। विभिन्न कारणों और प्रक्रियागत बाधाओं के चलते परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब इसे पुनः गति प्रदान की गई है तथा लगभग घ1,400 करोड़ की संशोधित विस्तृत अनुमान रिपोर्ट तैयार की गई है। श्री बिट्टू ने कहा कि यह रेल लाइन केवल क्षेत्रीय संपर्क को ही मजबूत नहीं करेगी, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में अमृतसरदृपठानकोट रेलखंड के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी कार्य करेगी,

सीएम मान की फर्जी वायरल वीडियो पूरी तरह से फेक, 1191 एंग्लों से की गई जांच

चंडीगढ़। वीरवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने प्रेस कांफ्रेंस में कथित वीडियो को लेकर दावा किया कि 1191 अलग–अलग एंगल से सीएम की बॉडी का विश्लेषण किया गया है, जिसमें चेहरे, कद–काठी और चाल–ढाल तक का अध्ययन शामिल है। आप नेताओं के अनुसार, रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वीडियो में सीएम भगवंत मान नहीं हैं, बल्कि किसी अभिनेता का इस्तेमाल कर वीडियो तैयार किया गया है। आप नेताओं ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं है। जांच के दौरान पता चला कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई करीब 5 फुट 10

इंच आंकी गई है, जबकि मान की लंबाई 5 फुट 8 इंच है जिसमें दोनों के बीच स्पष्ट अंतर मिला। साइड और बैक प्रोफाइल भी मुख्यमंत्री से मेल नहीं खाती। शरीर की बनावट, कंधों और पोश्चर में भी बड़ा अंतर मिला।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, सोमवार 24 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

आंगनवाड़ी केंद्र में लौटे बच्चों को दलित हेल्पर का बनाया खाना मिला

राजनगर २३/०८ (संवाददाता): केंद्रपाड़ा ज़िले के एक गांव के आंगनवाड़ी सेंटर में तीन महीने से चल रहा जाति का झगड़ा सोमवार को खत्म हो गया, जब ऊंची जाति के बच्चे सेंटर में वापस आए और एक दलित महिला हेल्पर का बनाया खाना खाया। रजिस्टर्ड 20 बच्चों में से 16 अपने माता-पिता के साथ घालिमाला ग्राम पंचायत के नुआगांव गांव के आंगनवाड़ी सेंटर आए और हेल्पर का बनाया खाना खाया, जबकि जो बच्चे नहीं आए, उन्होंने बीमार होने की बात कही।

शर्मिष्ठा सेठी, एक दलित महिला, को हेल्पर के तौर पर अपॉइंट करने के बाद से आंगनवाड़ी सेंटर पिछले साल 21 नवंबर से बंद था, और कई ऊंची जाति के परिवारों ने अपने बच्चों को सेंटर भेजने या प्रेग्नेंट महिलाओं और दूध पिलाने वाली मांओं के लिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पौष्टिक खाने की चीज़ें लेने से भी मना कर दिया था। जाति विवाद से पूरे देश में गुस्सा फैल गया, और यह मामला पार्लियामेंट में भी उठा, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने काम की जगह पर जाति के आधार पर भेदभाव पर चिंता जताई। सोमवार को, केंद्रपाड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपाली मिश्रा और राजनगर ब्लॉक धरुब चरण साहू बच्चों का स्वागत करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर पर मौजूद थे। मैंने बच्चों को रागी के लड्डू परोसे।

बाद में, मैंने चावल और 'दलमा' (सब्ज़ी की करी) बनाकर बच्चों को परोसा। उन्हें खाना खाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वे खिलौनों से भी खेले, जिससे सेंटर में जान आ गई, जो लगभग तीन महीने से वीरान पड़ा था, सेठी ने कहा। मुझे उमीद है कि गांव में जाति का भेदभाव अब अपना बुरा रूप नहीं दिखाएगा, उन्होंने आगे कहा। सीडीपीओ ने कहा कि बच्चों ने, अपने गार्जियन के साथ, सेंटर में खुशी के पल बिताए।

मिश्रा ने कहा, शर्मिष्ठा सेठी को हेल्पर बनाने पर कुछ गांववालों की असहमति की वजह से सेंटर लगभग तीन महीने तक बिना बच्चों के चला। अब, रौनक वापस आ गई है। जो बच्चे नहीं आए, उनके बारे में सीडीपीओ ने कहा कि वे ठीक नहीं हैं इसलिए वे नहीं आ सके। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि जो बच्चे नहीं आए थे, वे मंगलवार को सेंटर आएंगे क्योंकि झगड़ा सुलझ गया है। लोगों ने मतभेदों को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। यह खुशी की बात है। राजनगर के ब्लॉक धुरबा चा रान साहू ने कहा, यह मामला अब पुरानी बात हो गई है। मुझे उम्मीद है कि गांववालों के बीच भाईचारा बना रहेगा।

आरएसपी के छह कर्मचारियों ने 'आर.एस.पी. गौरव' पुरस्कार जीता

राउरकेला २३/०८ (संवाददाता): सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र के छह कर्मचारियों को सिविक सेंटर में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में 'आरएसपी गौरव' पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा ने पुरस्कार प्रदान किए।

वर्कमैन श्रेणी में इंजीनियरिंग एसोसिएट (लम्स एवं रिफ्रैक्टरी), श्री आयस्कंता साहू ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमश: इंजीनियरिंग एसोसिएट (न्यू प्लेट मिल), श्री अरूपानंद प्रधान और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट (कोक ओवन), श्री आसिफ हुसैन सिद्दीक को मिला।

कार्यपालक श्रेणी में, वरिष्ठ प्रबंधक (सेवाएं), श्री अनूप अग्रवाल ने पहला स्थान जीता। सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन), सुश्री संगीता एम सिंदूर को दूसरा स्थान मिला जबकि सलाहकार (चिकित्सा), सुश्री नेहा दास को तीसरा स्थान मिला। इस पुरस्कार के 8 वें संस्करण, जनवरी 2023 में मेरा आरएसपी - मेरा पहचान अद्वितीय पहल के तहत शुरू किया गया, जिसमें कर्मचारियों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो आरएसपी के साथ अपने मज़बूत बंधन को प्रदर्शित करता है। आरएसपी के 2762 कर्मचारियों ने आरएसपी पोर्टल कर्मचारी क्षेत्र (वेब और मोबाइल ऐप दोनों) में प्रविष्टियां बनाई। इनमें से 262 कर्मचारियों में 147 कार्यपालक अधिकारी और 115 श्रमिक शामिल हैं, जिन्होंने 17 जुलाई से 31 जुलाई, 2026 तक हर दिन आरएसपी के बारे में अपनी भावनाओं को साझा किया। इस पहल के हिस्से के रूप में, कर्मचारियों को दिए गए समय अवधि के दौरान हर दिन आरएसपी के बारे में सकारात्मक विचारों का कम से कम एक पूरा वाक्य लिखना आवश्यक था। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की पहचान गुप्त रखी गई और समिति ने रोज़ाना अपने अंक दर्ज किए। उनके मूल्यांकन के आधार पर, कार्यपालक और गैर- कार्यपालक दोनों श्रेणियों के शीर्ष तीन कर्मचारियों को आरएसपी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच गर्व की भावना को बढ़ावा देना और सकारात्मक सोच और संयंत्र के बारे में अच्छी बातें कहने की आदत को प्रोत्साहित करना था।

प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल पहुंचाने से पहले एंबुलेंस रोककर सो गया चालक, परिजनों ने लगाए आरोप

भुवनेश्वर २३/०८ (संवाददाता): ओडिशा गजपति जिले के आर. उदयगिरी क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही 108 एंबुलेंस बीच रास्ते में रुक गई, जिससे महिला का जीवन खतरे में पड़ गया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एंबुलेंस का चालक नशे में था। जिसके चलते उसे मजबूरी में निजी वाहन की व्यवस्था कर महिला को अस्पताल पहुंचाना पड़ा।

यह घटना गुरुवार देर रात की है जब महिला को चंद्रगिरी मेडिकल सेंटर से बरहमपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। रास्ते में चालक की संदिग्ध गतिविधियों ने परिजनों को परेशान कर दिया।मरीज के पति विजय राइता ने बताया कि एंबुलेंस चालक बेहद लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और वह नशे की हालत में नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि चालक ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और वहीं सो गया। हमें लगा कि मेरी पत्नी की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए रात करीब 1 बजे मैंने खुद एक निजी वाहन बुक कर उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया।विजय ने आरोप लगाया कि यदि समय पर अस्पताल न पहुंचते, तो गंभीर जटिलताएं हो सकती थीं ज़्योंकि महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी।हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने चालक के नशे में होने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह अचानक बीमार हो गया था, जिससे उसे वाहन रोकना पड़ा और वह सो गया। अस्पताल के प्रभारी ने कहा कि चालक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई थी, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी। नशे की बात निराधार है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों और पीड़िता के परिवार ने 108 एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं, 108 एंबुलेंस सेवा की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

स्टाफ की कमी के कारण रेडिएशन थेरेपी रुकी

संबलपुर २३/०८ (संवाददाता): वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बर्ला में क्वालिफाइड टेक्नीशियन की कमी के कारण पिछले छह महीनों से रेडिएशन थेरेपी बंद है, जिससे पश्चिमी ओडिशा के कैंसर मरीज़ प्रभावित हो रहे हैं जो इलाज के लिए इस सरकारी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सेवाओं में यह रुकावट पिछले साल अगस्त में रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के दोनों स्वीकृत पद खाली होने के बाद शुरू हुई, एक रिटायरमेंट के कारण और दूसरा इस्तीफे के कारण। रेडिएशन उपकरण चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना, रेडियोथेरेपी विभाग तब से इलाज देने में असमर्थ है। सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के कैंसर मरीज़ों के लिए मुख्य रेफरल सेंटर के रूप में काम करता है।

एलटीआर टीचर उमीदवारों का मेरिट लिस्ट में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन

भुवनेश्वर २३/०८ (संवाददाता):लीव ट्रेनिंग रिज़र्व टीचर (एलटीआर)पोस्ट के लिए कैंडिडेट हाई स्कूल टीचर भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तुरंत जारी करने की मांग को लेकर भुवनेश्वर में ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। लगातार आठवें दिन भी यह धरना-प्रदर्शन जारी रहा। एलटीआर भर्ती प्रोसेस 2023 में शुरू हुआ था, जिसमें आर्ट्स, ओडिया, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट्स में लगभग 6,025 टीचिंग पोस्ट्स की घोषणा की गई थी। रिजल्ट्स की घोषणा के बाद, 22 जनवरी, 2026 से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पूरा हुआ। हालांकि, वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म होने के बावजूद, OSSC ने अभी तक ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं की है, जिससे कैंडिडेट में निराशा बढ़ रही है।सैकड़ों कैंडिडेट ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है, खबर है कि एक हजार से ज़्यादा कैंडिडेट प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं।

प्रदर्शनकारी रात भर OSSC ऑफिस के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए थे। एक प्रोटेस्टर ने कहा, हम एक डेलीगेशन से मिले और हमें बताया गया कि मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुए आठ दिन हो गए हैं, फिर भी वेबसाइट या किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए कोई अपडेट नहीं आया है। एक और कैंडिडेट ने कहा, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं होता, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए जब तक ज़रूरी होगा, तब तक यहीं रहने के लिए कमिटेड हैं। यह प्रदर्शन ओडिशा में पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और समय पर कम्युनिकेशन की बढ़ती मांग को दिखाता है।

पुरी में अस्तारंगा तट से 10 फुट के मगरमच्छ को सुरक्षित बचाया गया

पुरी २३/०८ (संवाददाता): पुरी ज़िले में अस्तारंगा तट पर दिखे एक बहुत बड़े मगरमच्छ को वन विभाग ने सफलतापूर्वक बचा लिया, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को राहत मिली। तटरेखा पर इस विशाल सरीसृप को देखने के बाद आस-पास के तटीय गांवों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ इलाके में आने वाले पर्यटकों में भी डर का माहौल बन गया था।

घटना के बाद, अस्तारंगा वन रेंज के अधिकारियों ने तुरंत पर्यटकों को चेतावनी जारी की और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तट पर गश्त बढ़ा दी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, मगरमच्छ का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए एक विशेष बचाव अभियान शुरू किया गया। लगातार दो दिनों तक, राजनगर रैपिड रिस्पांस टीम और अस्तारंगा वन रेंज के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने समुद्री रास्तों से मगरमच्छ की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी। टीम लगातार अलर्ट पर रही और सरीसृप पर नज़र रखती रही ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे लोगों या जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना बचाया जा सके। बचाव अभियान कल पीर जहानिया समुद्र तट के पास सफलतापूर्वक चलाया गया। जाल का इस्तेमाल करके, वन विभाग की टीम ने लगातार प्रयासों के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। बचाव के बाद, मगरमच्छ को भितरकनिका ले जाया गया, जहाँ वह एक उपयुक्त प्राकृतिक आवास में रहेगा। वन अधिकारियों ने पुष्टि की कि मगरमच्छ की लंबाई 10 फीट 6 इंच है और यह खारे पानी की मगरमच्छ प्रजाति का है। वन विभाग की समय पर कार्रवाई से तटीय निवासियों में सुरक्षा की भावना बहाल हुई, साथ ही मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से दूसरी जगह पहुँचाना भी सुनिश्चित हुआ।

इस्पात जनरल अस्पताल में 55 वर्षीय गंभीर सिर की चोट से पीड़ित मरीज 23 दिनों की चिकित्सा के बाद स्वस्थ हुआ

राउरकेला २३/०८ (संवाददाता): सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के इस्पात जनरल अस्पताल (आई.जी.एच.) के चिकित्सकों ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया। मरीज को अर्ध-बेहोशी की अवस्था में तथा सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई के साथ अस्पताल लाया गया था। आपातकालीन मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के बाद गहन चिकित्सा एवं पुनर्वास के माध्यम से मरीज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 23 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अब उसे छुट्टी देने की योजना है।

श्री बिरंची नारायण साहू 19 जुलाई 2026 को राउरकेला के सिविल टाउनशिप में एक वाहन की चपेट में आने से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें प्रारंभ में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां मस्तिष्क की सीटी स्कैन जांच में मस्तिष्क के ऊपर रक्त का गंभीर जमाव तथा मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चोट का पता चला। इसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आई.जी.एच. को रेफर किया गया। आई.जी.एच. पहुंचते ही मरीज को तत्काल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और आपातकालीन मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के लिए ले जाया गया। शल्य चिकित्सा वरिष्ठ परामर्शदाता न्यूरोसर्जन, डॉ. मनोज कुमार देव द्वारा की गई, जबकि एनेस्थीसिया संबंधी सहयोग अतिरिक्त सी.एम.ओ., एनेस्थीसिया, डॉ. संजुक्ता पाणिग्राही ने प्रदान किया। नर्सिंग ऑफिसर लिपिका ने ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सहयोग दिया। शल्य चिकित्सा के बाद मरीज को लंबे समय तक गहन चिकित्सा एवं वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी। सिस्टर शाइनी जॉर्ज के नेतृत्व में आई.सी.यू. टीम तथा नर्सिंग एवं क्रिटिकल केयर स्टाफ ने मरीज के स्वास्थ्य लाभ के इस महत्वपूर्ण चरण में लगातार निगरानी और देखभाल की।

धीरे-धीरे मरीज की स्थिति में सुधार होने लगा। उसे सफलतापूर्वक वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया और स्वास्थ्य लाभ के दौरान सांस लेने में सुविधा के लिए अस्थायी ट्रेकियोस्टॉमी की गई। स्थिति में और सुधार होने पर उसे आई.सी.यू. से वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। अगले कुछ दिनों में मरीज की चेतना के स्तर में लगातार सुधार हुआ। वह सरल निर्देशों का पालन करने लगा, बीच-बीच में अपने परिजनों से बातचीत करने लगा और धीरे-धीरे मुंह से भोजन लेने लगा। पर्याप्त मात्रा में भोजन लेने तथा स्वतंत्र रूप से सांस लेने में सक्षम होने के बाद अस्थायी ट्रेकियोस्टॉमी को सफलतापूर्वक हटा दिया गया।

वार्ड की नर्सिंग टीम, जिसमें गौरी, मानसिनी, मनीषा, नमिता, प्रियंका तथा अन्य समर्पित नर्सिंग कर्मी शामिल थे, ने मरीज के स्वास्थ्य लाभ के दौरान लगातार निगरानी, नर्सिंग देखभाल एवं सहयोग प्रदान किया। लंबे समय तक गंभीर बीमारी से जूझने के बाद मरीज की शक्ति एवं गतिशीलता वापस लाने में गहन एवं व्यक्तिगत फिजियोथेरेपी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिजियोथेरेपी की देखभाल श्री प्रेमानंद स्वाईं एवं उनकी टीम द्वारा की गई। 23 दिनों के अस्पताल में भर्ती रहने के बाद श्री साहू को होश आ गया, वे आसान निर्देशों का पालन करने लगे, पर्याप्त मात्रा में मुंह से भोजन लेने लगे और एक व्यक्ति के सहारे चलने में सक्षम हो गए। उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की योजना है।

यह मामला गंभीर सिर की चोट के उपचार में समय पर आपातकालीन हस्तक्षेप, उन्नत क्रिटिकल केयर, समर्पित नर्सिंग सेवा तथा सुव्यवस्थित पुनर्वास के महत्व को रेखांकित करता है। आई.जी.एच. की न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया, आई.सी.यू., नर्सिंग और फिजियोथेरेपी टीमों के समन्वित प्रयासों ने मरीज के स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण योगदान दिया।यह सफल परिणाम राउरकेला के इस्पात जनरल हॉस्पिटल में जटिल और जानलेवा ट्रॉमा मामलों के इलाज में मल्टी-डिसिप्लिनरी केयर के महत्व को दर्शाता है।